Debate in Parliament

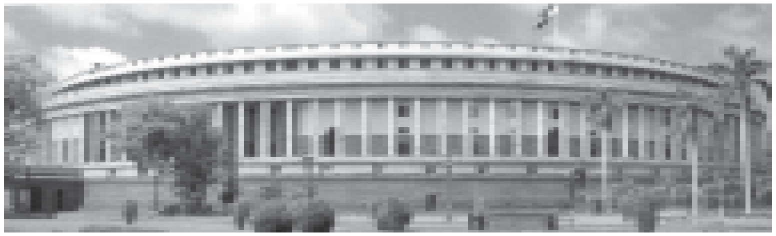

राष्ट्रमंडल खेल
COMMONWEALTH GAMES
महाघोटाला

DELHI 2010
XIX COMMONWEALTH GAMES

Are we ready ?

- कीर्ति आजाद
- अनुराग ठाकुर

BHARATIYA JANATA PARTY

Foreword

The commonwealth games are proving yet another embarrassment for the country. While the facilities for the games remain incomplete and preparations continue to falter at every step the reports of corruption is damaging the reputation of India. The daily reports of corruption, scams, money laundering, deception and loot is not only having demoralizing impact on our sportspersons, it is becoming very disheartening for the entire nation. It appears very alarming that the Congress led UPA government at the centre remains unmoved even in the face of clinching evidence of corruption and refuses to enforce law of the land in booking the authorities of the Commonwealth Organising Committee found involved in scams. It cannot be now denied that the systematic loot of public money in the name of hosting commonwealth games in the country as reported in media has the backing of Congress led UPA government.

The nation had great expectations by hosting the commonwealth games. It was expected that hosting the event will boost the morale of the sportspersons in the country for whom latest facilities and infrastructure would be created and India's reputation will increate in the eyes of international community. But all these expectations stand belied and an environment of gloom is engulfing the nation. Commonwealth games have become another den of corruption and loot.

In the parliament Bharatiya Janata Party raised the issue of corruption in commonwealth expressing the concern of the nation regarding the bungling and scam taking place in the name of commonwealth games. Shri Kirti Azad and Shri Anurag Thakur raised the issue in the Lok Sabha. We are publishing the text of their speech in this booklet. We hope that this booklet will help our reader in understanding the various issues related to controversies that continue to plague commonwealth games.

Publisher,
Bharatiya Janata Party
11, Ashoka Road, New Delhi

August 2010

लोकसभा

राष्ट्रमंडल खेल उर्फ भ्रष्टमंडल खेल

dhfrl vktkn

कामनवैल्थ गेम्स में 24 देशों से दूल्हे आने वाले हैं जिनमें से 40 देश ऐसे हैं जिनका पूरे वर्ष का वित्तीय खाता, जो हमारे यहां लाखों का बनता है, वहां हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है। दूल्हे को बुलाने के लिए 54 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, इतना दहेज दिया है। कहीं ऐसा न हो कि उसे न वहां दुल्हन दिखे, न मंडप दिखे और न बारात घर और जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती, यह बोलते हुए वह वापिस चला जाए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वालों की दिल्ली, लूट–खसोट, भ्रष्टाचार, अब राष्ट्र मंडल खेलों को भ्रष्ट मंडल खेल कहा जा रहा है, राष्ट्र मंडल उर्फ भ्रष्ट मंडल खेल।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के राष्ट्रमंडल खेल विश्वभर में न भूतो न भविष्यती होने वाले हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार न भूतो न भविष्यति। दिनदहाड़े लूट न भूतो न भविष्यति। हमारी यूपीए–1 की सरकार के खेल मंत्री, ऐसे खेल मंत्री विश्व में न भूतो होंगे न भविष्यति। यह शायद पहले ऐसे खेल मंत्री थे, जिन्हें खेलों से कोई मतलब नहीं था। उनके अनेकों वक्तव्य हम रोज़ पढते रहते हैं। मुझे खिलाड़ी होते हुए बहुत खेद है और हमारे बीच में जितने भी व्यक्ति यहां हैं, कभी न कभी बचपन से बड़े होते हुए अपनी जिंदगी में कोई न कोई खेल अवश्य खेले होंगे। उन्होंने कहा कि यह खेल जो कर रहे हैं, वे शैतान हैं। उन्होंने कहा कि यह खेल जो रहा है, यह केवल लूटपाट है। मैंने परसों उनका एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत ही गंभीर वक्तव्य है। अभी तक एससीएसटी के स्पेशल प्रोविज़न के फण्ड आए थे, उसके डायवर्जन के

बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से रखी थी। वह आग अभी तक ठण्डी नहीं हुई है और एक और वक्तव्य यूपीए एक के खेल मंत्री द्वारा आया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर वक्तव्य दिया है। मैं सरकार से यह जानकारी चाहूंगा कि इन सब का जवाब कौन देंगे? अगर खेल मंत्री जी से पूछें तो वे कहते हैं कि मेरा काम तो साई के जो स्टेडियम बनाने हैं, वहां तक है। अरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर से पूछें तो वे कहते हैं कि मेरी एजेंसियों ने जो काम करना है, मैं वहां तक हूं। दिल्ली सरकार से पूछें तो वे कहते हैं कि हमें जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हम वहां तक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह गंभीर वक्तव्य यूपीए–1 के खेल मंत्री, माननीय मणिशंकर अय्यर जी ने परसों दिया है। एक गोष्ठी हुई थी और वह गोष्ठी 21वीं सदी के पत्रकारिता तथा भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर की गई थी। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा, उन्होंने जो कहा, मैं उसे कोट करना चाहता हूं कि अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने के लिए भारत 40 करोड़ किसान परिवारों की कर्ज माफी के लिए रखे गए 70 हजार करोड़ रुपए में से आधा कॉमनवैल्थ गेम्स पर खर्च कर रही है। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। उन्हें किस बात की नाराजगी है? आज वह सरकार के ऊपर, जिस सरकार में वह खेल मंत्री थे, आरोप पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। आज तक किसी ने जानकारी नहीं दी, किसी ने यह जानने की कोशिश की कि स्टेडियमों की क्या हालत है। क्या हम अपनी नाक, इज्जत बचा पाएंगे? यूपीए की सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है कि हमने 70 हजार करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ किए थे। मैं सरकार से इसका जवाब अवश्य चाहूंगा कि उन्होंने यह जो वक्तव्य दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है? वित्त मंत्री जी को बहुत जवाब देने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि एक दिन एक टेलीविजन चैनल पर सीवीसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ, सीएनएन आईबीएन चैनल था, उसने सीवीसी रिपोर्ट का खुलासा किया। ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट थे, क्यों आया, कौन लेकर आया, मुझे मालूम नहीं। कौन घर का भेदी था, जो लंका ढहा रहा था? यह रिपोर्ट सीवीसी की आई, जिसके अंदर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, एलजी का डीडीए और सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, उनके द्वारा की गई करोड़ों अनियमितताओं के बारे में खबर थी। टेलीविजन पर यह भी देखा गया कि सीवीसी के एक सदस्य भी आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे पास सीवीसी में आए थे। जब मैं छोटा था तो मुझे जेम्स बॉंड के सिनेमा देखने

का बड़ा शौक था। उसमें जेम्स बॉंड एमआई–6 का इंग्लैंड का एक सिपाही है, उसके पास लाइसेंस टू किल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाइसेंस टू करप्शन मांगने के लिए सीवीसी के पास सरकार की तरफ से कौन गया था? ये बातें भी सामने आईं। क्या यह केवल एक संयोग था या मैं यह कहूं कि सरकार में बैठा हुआ दूसरा धड़ा, जो एक धड़े को नहीं चाहता, 24 घंटे के अंदर एक दूसरे न्यूज़ चैनल टाइम्स नाऊ पर, तीन महीने पहले उनके पास, उनके खेल मंत्रालय में वह चिट्ठी पड़ी थी कि आर्गनाइजिंग कमेटी द्वारा बेटन रिले में गड़बड़ हुई, उसे छिपाने के लिए दी गई। यह मेरा गंभीर आरोप इस सरकार पर है, मैं सरकार से इसका जवाब चाहूंगा। ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट का हनन हुआ, सीवीसी की रिपोर्ट में इनकी जो घोर अनियमितताओं सामने आई थीं, उन्हें छिपाने के लिए दूसरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी गई। मैं कोई आर्गनाइजिंग कमेटी का एडवोकेट नहीं हूं और न ही सरकार का हूं। जिस आदमी ने गलती की है, जिसने ये घोर अनियमितताएं की हैं, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसे लेकर सदन के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो सकता। सीवीसी की रिपोर्ट में घोर अनियमितताएं सामने आई हैं, उसमें बहुत कुछ कहा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जिनमें यहां तक कहा गया है कि जिसका दाम एक रुपया होना चाहिए था, उसके दाम 10 गुने ज्यादा बढ़ाकर टेंडर किए गए। वह रिपोर्ट मेरे पास है। जो काम एक रुपए में होना चाहिए था उसे 10 रुपए में कराने के टेंडर किए गए। एक नंबर का काम नहीं किया, 10 नंबर का किया, तो फिर सिनेमा का वही गाना याद आता है जिसमें कहा गया है कि दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी- ये जो कॉमन गेम्स हो रहे हैं, लोग सोचेंगे कि पूरा कॉमनवैल्थ गेम्स क्यों नहीं कहा जा रहा है, केवल कॉमन गेम्स ही क्यों कहा जा रहा है? वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉमनवैल्थ गेम्स में से वैल्थ तो गायब है, केवल गेम्स ही रह गए हैं। महोदय, सी.वी.सी. की बहुत गम्भीर रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यानी 2009 में वे 121 प्रोजैक्टों को देखने जगह–जगह गए और उन्होंने चैकिंग की तथा गुणवत्ता को देखा। इस वर्ष 57 जगहों पर गुणवत्ता को चैक करने गए। ऐसी एक भी ऐजेंसी नहीं है, जिसके ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाए हों, फिर चाहे वह एजेंसी, केन्द्र सरकार की हो या दिल्ली सरकार की। उन आरोपों को आप देखेंगे, तो जो व्यक्ति काला अक्षर भैंस बराबर हो या जिसे आप कहते हैं कि बछिया का ताऊ अगर उसके सामने भी आप इसे पढ दें, तो वह भी समझ जाएगा कि

यह क्या है।

महोदय, सी.वी.सी. की रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ में डी.डी.ए. के बारे में कहा गया है, जो सीधे लैफ्टीनेंट गवर्नर के अंडर में आता है। अब मैं लैफ्टीनेंट गवर्नर को तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वे तो राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं।

मैं कोट करना चाहता हूं– In the work related to CWG, the PQ application was submitted by consortium of four companies - चार कंपनियों के उन्होंने नाम लिए हैं– Mrs. Payce Consolidated Ltd., Australia; Paynter Dixon Construction Pvt. Ltd., Australia,. Sportina Exim Pvt. Ltd. Mumbai; and Robertson + Marks Architects Pvt. Ltd., Australia. तीन ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हैं और एक मुम्बई की है। As per the agreement to establish a consortium, the consortium members agreed to incorporate a limited liability company, that is, a Special Purpose Vehicle Company (SPV) in the name and style of "Sportina-Payce Construction (India) Pvt. Ltd." With the following financial stakes. सबके स्टेक के बारे में इसमें लिखा गया है कि किसका कितना शेयर था और किसके कितने पैसे थे। उसी में आगे जाते हैं। I quote again - The agency was pre-qualified on the basis of experience of Mès. Payce Consolidated Ltd. But at the time of submitting the tender, a company was formed as "Sportina Payce Infrastructure Pvt. Ltd." & उसका नाम बदल दिया गया। It submitted the tender and became L1. It is fair enough. And finally, work was awarded to them. The structure of the company". Sportina Payce Infrastructure Pvt. Ltd." Was different than the original stipulated consortium. सुनिएगा & in this other partners except. Sportina Exim Pvt. Ltd. were not represented at all. Ultimately at site only. Sportina Exim Pvt. Ltd. was executing the work - Sir, it is very important to note - which does not have expertise and experience, which was considered at the time of PQ. Thus, undue favour has been given to agency. यह रिपोर्ट है। इसमें केवल डी.डी.ए. के बारे में बताया गया है। मैं आपको ऐसी रिपोर्ट एक नहीं, अनेक बताऊंगा। ऐसे 30–30 आइटम्स थे, जो कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के पार्ट नहीं थे, भाग नहीं थे। उसके बाद भी टेंडर में उन्हें 20–20 गुना ज्यादा रेट देकर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। मैं अगर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ूं, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। इसके अन्तर्गत जो अनियमितताएं हुई हैं, उनमें एक और बड़ी मजेदार बात है कि - Award

of work to ineligible agencies - ineligible agencies were awarded the work - one Joint Venture (JV) firm was qualified based on a particular name and composition of the JV whereas bits submitted by the JV with different compositions were accepted. Work finally had to be terminated which resulted into time and cost overrun- सब के ऊपर है। एन.डी.एम.सी. के बारे में है। जो कम से कम 50 प्रतिशत गुणवत्ता होनी चाहिए, वह नहीं थी।

I quote:

"In the other case also, similar pattern of failure of the concrete samples were observed. In this case, all the concrete cubes failed when tested in the presence of the CTEO team."

सी.टी.ई.ओ. मतलब चीफ टैक्नीकल एग्जामिनर्स आर्गेनाइजेशन, जो कि सी.वी.सी. का ही भाग है, उन्होंने किया। It further says:

"All the concrete cubes failed when tested in the presence of the CTEO Team, out of which some exhibited the strength even lower than 50 per cent of the requirement, while others exhibited almost 60-80 per cent of the required strength."

अब मैं अगर इस पूरे प्रकरण को लेकर बैठकर पढने़ लग जाऊं तो शायद 26 अगस्त तक पूरा सैशन खत्म हो जायेगा और कोई चीज़ खत्म होने को नहीं आयेगी। जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो स्टेडियम्स 2003 में हमने 326 करोड़ रुपये का बिड किया था, टोटल बिड जो की गई थी, वह 1566 करोड़ की थी। हमारी यू.पी.ए.–2 के समय जो खेल मंत्री थे, उनके समय में 3566 करोड़ रुपये का बजट एप्रूवल हमको कैबिनेट से मिला, यानि 100 प्रतिशत ज्यादा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2007 में ही अगर हम कोई कार्यक्रम करना, स्टेडियम्स बनाना शुरू करते तो क्या यह परिस्थिति हमारे सामने होती? सी.वी.सी. की रिपोर्ट में आई हुई इन अनियमितताओं के बारे में कौन जिम्मेदार है। आज मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आज तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। मुझे एक चीज़ यह समझ में नहीं आती, सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई कोआर्डीनेशन ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर और वीरेन्द्र सहवाग साथ में खेलें और तालमेल न हो तो रन आउट होना तो स्वाभाविक है। आज वही परिस्थिति यहां पर बनी है और इस तालमेल को बिठाने के लिए मैं इन्फोर्मेशन यह आपके सामने रखता हूं। पब्लिक इन्फोर्मेशन ब्यूरो है और उसके अन्दर

तालमेल बिठाने के लिए जनवरी में तत्कालीन एच.आर.डी. मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी ने 29 जनवरी, 2005 को अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाया। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अलग–अलग निर्णय लिए गये। जैसे सबसे पहले जो मैं पूछता हूं, जिम्मेदारी किसकी है और माननीय खेल मंत्री जी उस जिम्मेदारी से कहते हैं, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो मुझे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाने हैं, वह देखूंगा। आपके अनेकों बार मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं। आपको ध्यान होगा कि कंसलटेटिव कमेटी में हम बैठे, तब भी हम लोगों ने इस विषय पर बहुत गम्भीर चर्चाएं की थीं। आपको लेकर व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं, लेकिन जो कमेटियां बनीं, उसमें सबसे पहला दायित्व आपके ऊपर ही बनाया गया। सबसे पहली कमेटी थी– To constitute an apex committee to be headed by the Sports Minister, which will have the overriding powers and responsibilities for overseeing and coordinating the Commonwealth Games. The minutes of all the other committees, related to the conduct of the Commonwealth Games, 2010 shall be submitted to the apex committee periodically for its information. The Chairman of the apex committee can also call for such information which it deems fit and can give such guidance that may be required. The Chairman of the apex committee may be kept informed by all the other committees whenever any major decision is taken.

29 जनवरी, 2005 और यह सरकार से मैंने उतारा है।

गुरू द्रोणाचार्य के सामने मैंने अपनी यह बात रख दी। दूसरे कृपाचार्य महाराज–महाभारत से कुछ सीखो। जिन्होंने हस्तिनापुर लूटा, उन्होंने लुटवा दिया। दूसरे कृपाचार्य जी महाराज–इसमें कहा थाः मुझे आगे बोलने दीजिए, तो मैं बताता हूं।

To constitute three -member sub-Committee of the GoM headed by the then Finance Minister, Shri P. Chidambaram, to supervise the deal with all financial matters.

यह उसी दिन का है। मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं, सारी उसी दिन की बता रहा हूं। जिस दिन उन्होंने बनाया था, गुरू कृपाचार्य अब तो प्रणव जी हो गए, चिदंबरम जी अब गृह मंत्रालय में आ गए। प्रणव जी इसमें आए हैं, तो वही बतायेंगे कि क्या घोटाला हो रहा है? यह संदिग्ध आरोप है कि कोर्डिनेशन नहीं बना पाए, जब 29 जनवरी, 2005 को कमेटियों का गठन किया गया, यह रही गुरू कृपाचार्य जी की बात। अब बात करते हैं,

आंख में पट्टी बांधे हुए गांधारी की – दिल्ली सरकार।

There will be a sub-Committee headed by the Chief Minister of Delhi which will look after all other issues that come under the jurisdiction of the Government of NCT of Delhi as pre the Constitution. कांस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ी हैं, द्रोपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन कोई भगवान कलयुग में आने वाले नहीं हैं, कोई भी यदुवंशी नहीं हैं, जो बचा लेंगे। मुलायम सिंह जी, अब आइए शकुनि पर, जिन्होंने चौसर खेलकर हस्तिनापुर को लुटवा दिया।

अब शकुनि पर आ जाएं। कमेटी आफ सेक्रेटरीज, इसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अपने को प्रजातंत्र के वाचडॉग कहते हैं, बांध रखा है, रख छोड़ा है, देश की किस्मत, लाल फाइलों और फीतों पर, उनकी यह कमेटी है। A Committee of Secretaries headed by the Cabinet Secretary will be responsible for the implementation of the decisions of the GoM regarding the Commonwealth Games. "

गुरू द्रोण जनवरी 29, 2005 आपको समर्पित करता हूं। इनके फंक्शन्स क्या थे? इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। इन लोगों को मीटिंग्स करनी थीं। फंक्शन जिनको करना था, माननीय कलमाड़ी जी यहां उपस्थित हैं। Commonwealth Games Federation- owner of the Commonwealth Games, बिल्कुल समझ में आता है। Organising Committee (OC), a society registered in February 2005, bears primary responsibility for successful conduct the Games. करेक्ट, स्टेडियम हैंड ओवर करें। गवर्नमेंट आफ इंडिया, सबसे ऊपर नाम है, the Ministry of Youth Affairs and Sports will be the nodal Ministry for the Government of India for the Games. मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं। मैं एक खिलाड़ी हूं और यह हमारे खेल मंत्री हैं। वह जब बयानबाजी करते हों कि मुझे केवल अपने साई के स्टेडियम से मतलब है, दूसरे से नहीं, तो एक खिलाड़ी होने के नाते टीस होती है, दर्द होता है, इसलिए मैं आपसे इस विषय पर अवश्य नाराज हूं। Group of Ministers will be responsible for the apex level policy decisions. ओबिवियसली प्रणव दा ही होंगे, क्योंकि चिदंबरम जी तो वहां नहीं हैं। उनको वह हेड करना था, सारे फाइनैंशियल देखने थे। वह कहां हैं? मुझे मालूम नहीं है, किंतु इस गड़बड़ घोटाले का हिसाब तो अंततः वही करके देंगे। The Committee of Secretaries Chaired by the Cabinet Secretary will be responsible for monitoring implementation of policy

decisions. Government of India, Lieutenant Governor, उनका नाम मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह सीधे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। अगर नाम बोलूं तो मुझ पर न कुछ गड़बड़ हो जाए। Lieutenant Governor will have the overall responsibility for work being executed by the Delhi Government with specific reference to security, law and order and matters coming under DDA. Chief Minister's Committee will be responsible for decisions on infrastructure and other activities within the jurisdiction of Delhi Government. Empowered Committee chaired by the Chief Secretary will be responsible for overseeing projects implemented by the Delhi Government and its agencies.

सबको अपने–अपने काम दे दिए गए हैं। कई ऑनर्स उनके रहे हैं, अलग–अलग सरकार की एजेंसियां हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, डीडीए है, एनडीएमसी है, म्युनिसिपल कारपोरेशन देलही, पब्लिक कोच डिवीजन देलही, गवर्नमेंट इंजीनियर्स इंडिया फलां–फलां, मतलब आप सुनते रहिए और सुनते चले जाइए। मैं केवल यह जानना चाहता हूं जब हम यहां पर भारत सरकार के विभागों के बारे में और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में किए गए गोलमाल और भ्रष्टाचार की चर्चा के लिए बैठे हैं कि क्यों इस प्रकार से हमारी नाक विश्व भर में कट रही है? मैं जानना चाहता हूं कि इन कमेटीज़ की कितनी मीटिंग्स हुईं? जो कमेटीज़ जनवरी, 2005 में फॉर्म कर दी गई थीं, 2005 से 2010 तक क्या इनके सामने अनियमितताएं नहीं आईं? क्या इनके पास रिपोर्ट्स नहीं आईं? यदि नहीं आई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और यदि आईं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो कौन जिम्मेदार है? मुझे मन में संशय है कि माननीय खेल मंत्री इन सब विभागों का मिलाकर जवाब दे सकेंगे। सीवीसी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट और अखबारों में रोज जो निकलता है, कितना पढ़ूं, पढता चला जाऊंगा, इतनी सारी कटिंग्स हैं, क्या दिखाऊं, किस–किस विषय पर बात करूं। हमारे पास एक से एक कटिंग्स पड़ी हैं और रोज लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से सबके मन में यह टीस है वह सीवीसी की रिपोर्ट। लाइसैंस टू करप्शन मांगने कौन गया था, उसका जवाब माननीय खेल मंत्री हमें अवश्य दें, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हाई पावर कमेटी बन जाने के बाद इनका आपसी तालमेल क्या था? अगर मैं यह कहूं कि इनका तालमेल चल रहा था और आंख पर गांधारी की तरह पट्टी बांधकर भ्रष्टाचार हस्तिनापुर को लुटते हुए देख रहे थे, तो उसके लिए यह सरकार

जिम्मेदार है और मैं पूरे अदब के साथ इनके ऊपर यह आरोप लगाता हूं। क्या इन्हें मालूम नहीं था कि उस कमेटी में क्या हो रहा है? हाई लैवल कमेटी की आपस में बैठकर जो बातें हो रही थीं, क्या उनके बारे में नहीं मालूम था? क्या यहां बैठे हुए माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन सबमें कमजोर कड़ी कौन थी? किसके कारण इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने आता रहा? माननीय मंत्री जी कहते रहे, It is a big Indian fat wedding. उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय इंडियन फैट वैडिंग में दो नम्बर का पैसा बहुत उपयोग होता है। वहां किस तरह पैसे लुटाए जाते हैं, यह किसी को मालूम नहीं है। अगर यही अभिप्राय माननीय खेल मंत्री का था कि बिग फैट वैडिंग में न जाने क्या–क्या होता है, इसलिए हमें आंख बंद करके सब कुछ देख लेना चाहिए, तो मैं गांधारी बनकर बैठ कर सब कुछ नहीं देखने वाला हूं। मंत्री जी, न दुलहन है, न मंडप है और न ही बारात घर है। आप बारात का स्वागत कहां करेंगे? खिलाड़ियों को होम एडवांटेज नहीं है, आपके स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम बारात का स्वागत करने वाले हैं। वह बारात कहां आएगी? मंत्री जी इस बात का जवाब अवश्य देंगे कि ये उस बिग फैट वैडिंग की बारात कहां बुलाने वाले हैं। कामनवैल्थ गेम्स में 24 देशों से दूल्हे आने वाले हैं जिनमें से 40 देश ऐसे हैं जिनका पूरे वर्ष का वित्तीय खाता, जो हमारे यहां लाखों का बनता है, वहां हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है। दूल्हे को बुलाने के लिए 54 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, इतना दहेज दिया है। कहीं ऐसा न हो कि उसे न वहां दुल्हन दिखे, न मंडप दिखे और न बारात घर और जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती, यह बोलते हुए वह वापिस चला जाए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वालों की दिल्ली, लूट–खसोट, भ्रष्टाचार, अब राष्ट्र मंडल खेलों को भ्रष्ट मंडल खेल कहा जा रहा है, राष्ट्र मंडल उर्फ भ्रष्ट मंडल खेल। हुसैन बोल्ट जो दुनिया के सौ मीटर के सबसे तेज धावक हैं, वह नहीं आ रहे हैं, वह घबरा गए हैं कि भ्रष्टाचार की सौ मीटर की दौड़ में करोड़ों के नोट लोग ऐसे सैकिंडों में गिन रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। अच्छे–अच्छे बड़े खिलाड़ी आने से मना कर रहे हैं। हम यहां अभी तक केवल मंडप सजाने में लगे हुए हैं। मंडप सजे नहीं, दुल्हन तैयार नहीं हुई और इस प्रकार की परिस्थिति सामने खड़ी कर दी गई है। स्टेडियमों का चीर हरण हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है।

मैं सैंट्रल हाल में बैठा था तो पीछे बैठे सदस्य बात कर रहे थे, मैं

अजहरूद्दीन जी का नाम नहीं लूंगा, कोई और थे, वहां बैठे चिन्तित थे। उन्होंने कहा कि आपने जो बात कही है, यह बहुत सही कही है।...

मैं सैंट्रल हाल में बैठा था। शुक्रवार को जब शून्य प्रहर में कामनवेल्थ गेम्स को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई तब आदरणीय जयपाल अंकल को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उसका कारण यह था कि हम नहीं चाहते थे कि इतनी बात हो गयी, जवाब मंत्री जी ने दे दिया और बात खत्म हो गयी। उसके बाद मैं सैंट्रल हाल गया, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सराहना की कि आपने खिलाड़ियों के बारे में जो बात की है, वह सच में बहुत मार्मिक बात है। मैंने उनसे कहा कि मुझे खेद इस बात का है कि जिस प्रकार का होम एडवांटेज हम खिलाड़ियों को स्टेडियम में मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। जो खिलाड़ी यहां आकर अपने आपको इस वातावरण में मिला सकें, समझ सकें, उनको वह अवसर नहीं मिला है। ऐसे में मुझे डर है कि क्या हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब नहीं होगा, तो तपाक से सत्ता पक्ष की एक सदस्या बोल पड़ीं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि घबराइये नहीं, सारे मैडल्स हमें ही मिलने वाले हैं। मैंने पूछा कि कैसे, आप यह कैसे कह सकती हैं? उन्होंने कहा कि जब दूसरा कोई आयेगा ही नहीं, तो सब मैडल्स हमारे ही होंगे। ...(व्यवधान) आप स्टेडियम की परिस्थिति समझ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कहा कि हमने 11,494 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जबकि सीएजी कहती है कि 12,888 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जो घपला हो रहा है, वह हमारे सामने है, लेकिन बीच में एकाउंट का जो सस्पेंस है, जो 1500 करोड़ रुपया है, वह कहां खर्च हो रहा है, यह अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 12,888 करोड़ रुपये खर्च करने के बारे में कहा है। यह अंतर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के 11494 करोड़ रुपये का है। मेरे पास अनेकों आंकडे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब हम कुछ स्टेडियम्स के बारे में भी बात कर लें। हिन्दुस्तान में लगभग 19 से 20 क्रिकेट स्टेडियम हैं। वे सब एक से एक सुन्दर और आधुनिक स्टेडियम्स हैं। अभी नागपुर में सबसे नया स्टेडियम बना है। फिरोजशाह कोटला में भी एक स्टेडियम बना है।

उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर का स्टेडियम 90 करोड़ रुपये में बना है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय खेल मंत्री, आदरणीय जयपाल अंकल, आप अवश्य जायें। अगर सरकार नहीं भेज सकेगी और आप कहेंगे, तो मैं अपने खर्चे में भेजूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जाकर उस नागपुर के स्टेडियम को देखिये।

स्टेडियम्स बनते हैं और इन स्टेडियम्स की 45 हजार कैपेसिटी है। हमारे पास एक जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 73 हजार थी, लेकिन उसे घटाकर 65 हजार कर दी गयी है। उस स्टेडियम को यदि बनाया जाये और इन स्टेडियम्स से तुलना की जाये, तो 90 का दुगुना 180, 180 के बजाय 270 और 270 के बजाय 300 करोड़ रुपये। अब 300 करोड़ रुपये में एक नया स्टेडियम जवाहर लाल नेहरू जैसा स्टेडियम खड़ा हो सकता है, लेकिन रेनोवेशन के लिए 961 करोड़ रुपये खर्च हुए।

मैं कहता हूं कि मैं सबसे छूट दे दूं, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में और 300 करोड़ रुपये का स्टेडियम कहूं, मैं यह भी कहूं कि उसमें सिंथेटिक टर्फ लगाना था, लाइटें तो वहां पहले से, शुरू से, 1982 से ही मौजूद हैं। वहां सिंथेटिक टर्फ लगाना था, कुछ दूसरे काम करने थे, ये सब काम देखकरके आदमी 100 करोड़ रुपये और लगा ले, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि खेल नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। 961 करोड़ रुपये का रेनोवेशन? मुझे समझ नहीं आया कि वहां सोना या चांदी लगाया गया है या हीरे–जवाहरात वहां मढ़े गए हैं जिसके लिए 961 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वेलोड्रम, जहां साइकिल चलती है। यह खेल मैंडेटरी है। वेलोड्रम बनाया सीमेंट का, जब लोगों ने कहा कि अरे, यह आपने क्या कर दिया, कलमाड़ी जी जानते हैं कि वह सीमेंट का नहीं वुडेन का होता है। इन्होंने कहा, अरे गड़बड़ी हो गयी, तो इन्होंने वुडेन का बना दिया। आदरणीय मंत्री जी गए उसका उद्घाटन करने के लिए, तो वहां क्या स्थिति थी। जब कभी आप पहाड़ों पर गाड़ी लेकर जाएं, वहां वर्षा हो रही हो, तो जैसे झरने का पानी सड़क के बीच से निकलता है और आपकी गाड़ी चलती है, वही उस दिन वेलोड्रम का हाल था। इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप यह है कि उसके डिफक्टिव नेचर के कारण अभी तक उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जो शूटिंग रेंज गुड़गांव में बनाई गयी है,..

महोदय, इन्होंने यह कहकर शाबासी लुटवा ली कि वहां अंतर्राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं, लेकिन क्या हमारे एथलीट्स को इन सारे स्टेडियम्स में से एक भी मिला है, जहां वे प्रैक्टिस करके होम एडवांटेज ले सकें। क्या गुडगांव में जो शूटिंग रेंज बन रही है, उसकी डिफेक्टिवनेस के बारे में कोई सामने आई है या नहीं या यहां पर जो करने सिंह शूटिंग रेंज के बारे में बात सामने आई है या नहीं आई है? साइकिलिंग का खेल मैंडेटरी है, आप इन बातों का उत्तर एक साथ दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन बातों पर पर्दा न डालें,

पर्दा उठा दीजिए। इन खेलों में साइकिलिंग अनिवार्य है। मैंने साइकिलिंग का इतना नाम नहीं सुना था, लेकिन समस्याओं के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था, इसलिए मैंने इंडियन ओलम्पिक एसोशिएशन का वेबसाइट खोला और उसमें से साइकिलिंग फेडेरेशन और इंडिया की वेबसाइट पर गया। वहां साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सिर्फ नाम है, उसका न तो कोई पता है, न यह जानकारी दी गयी है कि उसके कौन से सदस्य हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले हैं? किसी को नहीं मालूम है? हम यह कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2003 में लेकर आए थे और आज ऐसी परिस्थिति बनी है।

मैं सबसे गंभीर बात यह कहना चाहता हूं कि हमने खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचा है? हमारे खिलाड़ी कहां गए? आज तेजस्विनी सावंत जीतकर आई हैं, सुषमा जी ने उस विषय को सदन में उठाया था कि उनको बधाई दी जानी चाहिए, इस पर सदन की ओर से बधाई दी गयी है। हम चाहते हैं जब वह यहां पर आएं, तो अपना जौहर दिखाएं। हम चाहते हैं कि सायना नेहवाल, जिसने थाइलैंड और मलेशिया में लगातार तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पधाओं को जीता और आज वह वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। आज सभी लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब वह आएगी, बैडमिंटन खेलेगी और देश का सिर गौरव से ऊंचा होगा। लेकिन क्या सोच सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी, जो विश्व भर में फतेह करके आ गई और उसे अपने ही घर में पनाह नहीं मिली, जहां जाकर वह प्रेक्टिक्स कर सके। आज शूटिंग रेंज पर प्रेक्टिक्स का क्या हाल है, फेडरेशन के लोगों और खिलाड़ियों ने कहा है कि हमें सामान नहीं मिल रहा है। यह बात दूसरी है कि मंत्री जी कहेंगे कि हम दे रहे हैं, हमने इतने पैसे दे दिए हैं। लेकिन उन्हें वह मिल नहीं रहे हैं, भले ही आपने दे दिए हों। वह माल भी कहां बीच में तैयार रहा है, हमें बताया जाए?

साइकलिंग फैडरेशन के लिए साइकल्स आई हैं या नहीं, यह भी नहीं मालूम। मैंने तो अपने उत्तर भारत के सभी सांसदों को कहा है, सामने के सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वे सब अपनी तरफ से एक–एक साइकल वैलोड्रम में ले जाकर डोनेट कर दें। डा. एस.पी. मुखर्जी स्वीमिंग पूल काम्प्लेक्स में एक लड़की जब तैरने गई तो उसका पैर टूट गया, मोच आ गई। वहां पर टाइल्स उखड़ कर बाहर आ गईं और यह सीवीसी की रिपोर्ट में भी है।

मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एस्क्लेटेड प्राइस, 17888 करोड़ रुपए, साई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मई, 2007 में 1000 करोड़ रुपए था, मई, 2009 में 2475 करोड़ रुपया हो गया यानि 148 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी की बात करना चाहता हूं। फंडिंग फार सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोक स्टेट गवर्नमेंट, मई, 2007 में 770 करोड़ रुपए, दिसम्बर, 2008 770 करोड़ रुपए, मई, 2009 में 4720 करोड़ रुपए यानि 513 प्रतिशत की वृद्धि। इसके अलावा ओवरलेज़ हैं और बीच में मिसलेनियस और हैं, जिनका पता ही नहीं हैं, ये 10–100 करोड़ रुपए से ऊपर हैं। ओवरलेज़ मंगाए गए, वे अभी तक लगे नहीं, वे ऐसी टेम्परेरी फिटिंग्स हैं, चाहे लाइट्स हों या दूसरी चीजें हो। उनके बारे में कोई हिसाब नहीं है।

इन खेलों के लिए अभी तक स्टेडियम्स तैयार नहीं हैं। यहां तक कि क्वीन ने भी अपनी तरफ से बहुत गम्भीरता जाहिर की है कि यह क्या हो रहा है। विदेश से माइक फेनेल आते हैं, जिनका भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी का भी रैंक नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली उनके लिए बंद हो जाती है। ऐसे बंद हो जाती है जैसे कि प्रधान मंत्री जी का काफिला जा रहा हो। मेरा गम्भीर आरोप है कि खेलों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इन राष्ट्र मंडल खेलों को भ्रष्ट मंडल खेलों की संज्ञा दे दी गई है।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मैं दिल्ली सरकार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली सरकार को 4720 करोड़ रुपए मिले। लोगों ने कहा कि दिल्ली बड़ी सुंदर बन रही है। संजय निरुपम जी टीवी पर कहते हैं कि दिल्ली का बड़ा विकास हो रहा है। दिल्ली का अगर बड़ा विकास हो रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 90 से 95 प्रतिशत पैसा तो इन स्टेडियम्स को बनाने में ही और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ही खत्म हो गया है। दिल्ली में तो आज भी बिजली की, पानी की दिक्कत है। हर तरफ टूटी सड़कें देखने को मिलती हैं, जलभराव की समस्या ज्यों की त्यों हैं। यमुना इतनी गंदी हो गई है कि मैं तो जयराम रमेश जी को कहना चाहूंगा कि जो गेम्स विलेज यमुना के ऊपर बनी है, वहां पर सावधानी का बोर्ड लगा दें कि सावधान! कृपया यमुना में न जाएं, नहीं तो आपको मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या स्वाइन फ्लू हो सकता है। सालों से यमुना कितनी गंदी है। मैं इसी क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मैं इस क्षेत्र का 1993 से 1998 तक विधायक भी रहा। इस क्षेत्र में आज भी ग्राउंड वाटर को मिलाया जा रहा है, तब भी केवल चार–पांच घंटे तक गोल मार्केट क्षेत्र में पानी आता है।

ऐसा खारा पानी जिसे बच्चे और बूढ़े लोग नीचे आकर भरते हैं। यहां रोज बिजली जाती है और आप कहते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ ऱहा है। 961 करोड़ रुपये जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम में, 669 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, 214 करोड़ रुपये शिवाजी स्टेडियम में आपने केवल रैनोवेशन के लिए लगाए। समझ में नहीं आता है कि यह कैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डिवेलपमेंट हो रहा है? मेरा माननीय जयराम रमेश जी से अनुरोध रहेगा कि सावधान की पट्टी अपने खिलाड़ियों के लिए अवश्य लगाकर रखें।

विद्यार्थियों से होस्टल्स खाली करवा दिये गये हैं। दूरदराज से आने वाले विद्यार्थी यहां पढ ऩहीं पा रहे हैं। उनसे दस–दस गुना किराया वसूला जा रहा है लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थियों का होस्टल बंद करने के बाद भी तैयार नहीं है।

माननीय कपिल सिब्बल जी नोट करें कि वहां पर अभी तक 50 प्रतिशत भी कोई जगह तैयार नहीं है जहां पर आपने लगभग ढाई हजार बाहर से आकर खेलने वाले खिलाड़ियों को ठहराना है। आज यह परिस्थिति विद्यालयों की बनी हुई है।

डीडीए ने पांच हजार फ्लैट्स बनाने थे, सीधे उपराज्यपाल के अधीन थे, सीवीसी की रिपोर्ट मैंने आपको पढक़र सुनाई। आज कहते हैं कि हम केवल 1500 फ्लैट्स तैयार करके देंगे। जगह–जगह से जो लाइन्समैन आयेंगे, एम्पायर्स आयेंगे, ये तकनीकी लोग ठहरेंगे कहां?

टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से, पता नहीं माननीया शैलजा जी ने मंगाया है या फिर दिल्ली सरकार ने मंगाया है, एक हजार करोड़ का समान पांच हजार फ्लैटों के लिए आ चुका है, केवल यह 1500 फ्लैट्स देंगे, तो बाकी सामान का क्या होगा, समझ में नहीं आता है कि कहां काम आयेगा? आज यह परिस्थिति बनी है।

सीपीडब्ल्यूडी ने एक आरोप ऑरगेनाइजिंग कमेटी पर लगाया है। वह कहते हैं कि विलम्ब का कारण यह है कि जिस समय हम स्टेडियम बना रहे थे उस समय हमारे पास बार–बार ऑरगेनाइजिंग कमेटी के लोग आते थे और कहते थे कि थोड़ा सा डिजाइन में यह बदलाव कीजिए, थोड़ा सा वह बदलाव कीजिए। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने के कोई फायदा होने वाला नहीं है। डीजीसीपीडब्ल्यूडी माननीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत सीधा आता है, क्या यह बदलाव स्टेडियमों में किये गये या नहीं। अगर यह बदलाव किये गये तो क्या उसकी प्रोपर बिल्डिंग प्लॉन सैंक्शन

कराये गये या नहीं कराए गये?

करना क्या है, वह तो हम शुरु में ही बता चुके हैं। जो लोग गलत हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए और उसके साथ में यह जो घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए। जेपीसी की जांच हो, सीबीआई इंक्वायरी हो और जो गलत है, मैं सरकार से कहता हूं कि यह हो या वह हो, हमने आईपीएल गेट जो हुआ, उसके अंदर भी सरकार का रवैया देख लिया – न तो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, न ही जेपीसी हुई। पहला मेरा कहना है कि जेपीसी बैठाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। आप सभी सदस्यों के पास एक चिट्ठी आई होगी, उसमें लिखा होगा कि एक्रीडेशन कार्ड बनाने के लिए अपना फोटो और कार्ड दें। अब पता नहीं कि खेल होंगे या नहीं होंगे, अगर हो गये तो वह कार्ड आप अपना बनवा लीजिए। कम से कम इन स्टेडियम्स के टायलेट्स में जरूर जाइएगा, क्योंकि साढ़े चार हजार रुपए का टायलेट रोल है। उसे इस्तेमाल करके देखिएगा कि जो रोल तीस रुपए में मिलता है उसमें और इस साढ़े चार हजार रुपए के रोल में क्या फर्क है।

Sir, in the end, and Dr. M.S. Gill would agree with me, I would say that I think there is too much of politics in sports. I suppose we should bring in some sportsmanship into politics. That is what I intend to do as far as I stay as an elected representative. साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी को पूर्व मंत्री ने कैटल क्लास सर्वजन को कहा था। मैं केवल उसमें थोड़ा–सा सुधार लाना चाहता हूं। सरकार द्वारा खेलों में किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि this Government is all cattle but no class. Thank you.

■■

राष्ट्रमंडल खेल में लुट रही है जनता की गाढ़ी कमाई

vu|jkx Çlg Bkd|j

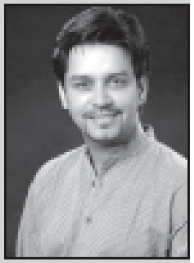

हम कामना करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन हमारे देश में होगा, लेकिन आज खेल के नाम पर धांधलियां, भ्रष्टाचार और अपव्यय की जो जानकारियां रोज–रोज सामने आ रही हैं, क्या वह चिन्ता का विषय नहीं है ? आयोजन समिति, दिल्ली सरकार, खेल मंत्रालय की भूमिका क्या गैर–जिम्मेदाराना नहीं रही ?

सभापति महोदया, मैं पूर्व में एक खिलाड़ी रहा हूं, खेल प्रबंधक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष और ओलम्पिक संघ का महासचिव भी रहा हूं। मैं खेलों के साथ बड़ी करीबी से जुड़ा हूं और हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संघ के महासचिव होने के नाते उसका सदस्य भी हूं। एक खिलाड़ी और खेल प्रबंधक होने के नाते, खेलों के साथ इतना करीबी रिश्ता होने के नाते मेरा यह मानना है, आज हिन्दुस्तान का हर नागरिक चाहता है कि खेलों का सफल आयोजन हो। मेरी पार्टी का भी लगातार यह स्टैंड रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन हो, क्योंकि इसका आयोजन देश की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदया, हम कामना करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन हमारे देश में होगा, लेकिन आज खेल के नाम पर धांधलियां, भ्रष्टाचार और अपव्यय की जो जानकारियां रोज–रोज सामने आ रही हैं, क्या वह चिन्ता का विषय नहीं है ? आयोजन समिति, दिल्ली सरकार, खेल मंत्रालय की भूमिका क्या गैर–जिम्मेदाराना नहीं रही ? सन् 2003 में इस देश को खेलों की जिम्मेदारी मिली, लेकिन वर्ष 2008 तक जो सैंक्शन्स हैं और एप्रूवल्स हैं, उन पर पांच वर्ष तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे रहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में किस पार्टी की सरकार रही ? वर्ष 2004 में यू.पी.ए. की सरकार आई। मंत्री जी ने कहा कि एन.डी.ए. के समय

में सैंक्शन्स हुईं।

सभापति महोदया, हमें इस बात की खुशी है कि अटल जी की सरकार ने 110 करोड़ की आबादी वाले देश में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को करने जिम्मेदारी ली, लेकिन उस समय खेलों के आयोजन का बजट लगभग 800 करोड़ रुपए का था, लेकिन जब बिडिंग हुई, तो उसमें 1899 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह बजट जो 800 करोड़ रुपए का था, आज कई हजार करोड़ रुपए का कैसे हो गया? क्या इसके लिए यू.पी.ए. की सरकार जिम्मेदार नहीं है ? पांच वर्षों तक क्यों फाइलों पर अधिकारी, खेल मंत्रालय के लोग और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य निर्णय नहीं ले पाए और अब इस देश की जनता की खून–पसीने की कमाई को लुटा रहे हैं और बजट को 1800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया? केवल फिगर्स को इधर–उधर करने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से खेल मंत्रालय और यह सरकार एक बिखरे हुए कुनबे की तरह है, उसी तरह फिगर्स को बांटकर बताया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में केवल कवर–अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महोदया, खेलों का आयोजन यहां इसलिए किया गया था कि 110 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल एक ओलम्पिक मैडल आता है, इसलिए सोचा गया कि एक जैन्यूइन प्रयास किया जाए कि इस देश के खिलाड़ी इस देश के लिए मैडल जीतकर ला सकें। अगर वर्ष 2006 में स्टेडियम बनकर तैयार हो जाते, तो हमारे एथलीट्स को यह सुविधा मिलती कि वे वहां प्रैक्टिस करते, जिससे आने वाले खेलों के दौरान उन्हें यह अहसास होता, उन्हें यह कॉन्फीडेंस होता कि हमने दो वर्षों तक यहां प्रैक्टिस की है, तो वे अपना प्रदर्शन अच्छे ढंग से कर पाते और मैडल जीतने के चांस ज्यादा हो जाते। एथलीट्स की ट्रेनिंग पर जो 687 करोड़ रुपए खर्च करने की जो ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन एथलीट्स की इन स्टेडियमों में कितने दिन ट्रेनिंग हुई, कितने दिन पहले आपने स्टेडियम तैयार कर के हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए?

महोदया, आज यहां बहुत सारी बातें हो रही हैं। श्री सुरेश कलमाड़ी जी हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस सदन के सदस्य भी हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे कुछ मसलों पर यहां सफाई दें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर आभारी रहूंगा, क्योंकि ओ.सी. कमेटीज की जो बातें यहां कही गईं, उनमें साफतौर पर आरोप लगे हैं कि खेलकूद के उपकरणों को खरीदने में जितनी कीमत आती, उससे कहीं ज्यादा उनके किराए पर खर्च किया जा रहा है। मैं कुछ उदारहण देना चाहता हूं। ट्रेड मिल को 7 लाख

रुपए में खरीदा जा सकता है, लेकिन उसका 45 दिन का किराया 9लाख 75 हजार रुपए दिया जा रहा है। एक्सरसाइज करने के बाद, आराम करने के लिए 8,500 से ज्यादा की कुर्सी, 100 लीटर का रैफ्रिजरेटर 42,202 रुपए में किराए पर लिए जाने की बात कही जाती है। खिलाड़ियों के विश्राम के छाते के लिए 6,308 रुपए की बात कही गई। टिश्यू रोल्स 4138 रुपए के। डीजल पॉवर की एक क्लस्टर में लागत 15 रुपए प्रति यूनिट बताई गई, तो दूसरे क्लस्टर में 80 रुपए प्रति यूनिट बताई गई है। 2 टन के ए.सी. का किराया 70,287 रुपए, तो वहीं पर दूसरी जगह 1, 87,597 रुपए बताया गया है। लिक्विड सोप डिस्पेंसर 200 रुपए का एक जगह, तो दूसरी जगह 10,000 रुपए का बताया गया है। स्विटजरलैंड की कोई एक कंपनी है, वह शायद उसी को 187 रुपए में दे रही है, लेकिन दूसरी ओर ब्रिटिश कंसोर्टियम नामक कोई कंपनी है, वह 9,379 रुपए में दे रही है। जो डिस्पेंसर, यानी जो कप हैं, हांगकांग बेस्ड कंपनी उसे 2 रुपए में दे रही है, तो दूसरी ई.एस.जे. बी. कंसॉर्टियम उसे 37 रुपए में दे रही है।

महोदया, मेरा केवल इतना कहना है कि ये सब बातें, जो रोज–रोज मीडिया में आती हैं, लोग पर्सनली मीडिया में जाकर इंटरव्यू देते हैं, यह ठीक नहीं है। यदि सबसे बड़ी जानकारी रखने का किसी को अधिकार है, तो इस संसद को है, इस हाउस को है। इसलिए उसकी पूरी जानकारी यहां मिलनी चाहिए। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जहां मैं एक ओर खेल के प्रबंधन के साथ जुड़ा हुआ हूं, वहीं दूसरी ओर मैं 17 लाख लोगों द्वारा चुनकर उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस सदन में आया हूं। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आज इस मुद्दे को उठाने पर विवश हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का मैं अध्यक्ष हूं। 48 करोड़ रुपये में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम रिकार्ड समय में हमने बनाकर दिया। आई.पी.एल. के मैचों का सफल आयोजन वहां पर करवाया। मुझे इस बात का दुख है कि जब इस सदन के बड़े सीनियर नेता जयपाल रेड्डी जी बात कर रहे थे... यह देश के 20 हजार करोड़ रुपये की बात है... यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, नहीं तो वैसे ही रह जायेगा कि 20 हजार करोड़ रुपये खर्च भी हुए और बाद में लोग हमें कहेंगे कि इस पर प्रकाश भी नहीं डाल पाये। मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, उसमें अगर 10 मिनट ज्यादा भी लग जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह जनता और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

अगर 48 करोड़ रुपये में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना सकता है, आई.पी.एल. के मैचेज़ का आयोजन करवा

सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं करवा सकती? इस देश की नामी–गिरामी एसोसिएशंस अगर क्रिकेट के क्षेत्र में, जिसको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि इन्दौर में 32 हजार कैपेसिटी का स्टेडियम 40 करोड़ रुपये में बना, हैदराबाद में 40 हजार की क्षमता का स्टेडियम 80 करोड़ रुपये में बना। धर्मशाला में 20 हजार की क्षमता का 48 करोड़ रुपये में, नागपुर में 45 हजार क्षमता का 84 करोड़ रुपये में और दिल्ली में 43 हजार की क्षमता का 85 करोड़ रुपये में बना तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा रैनोवेशन हुआ है, जो 961 करोड़ रुपये खर्च हुए? यह कोई छोटा एमाउंट नहीं है। 961 करोड़ रुपये जब खर्च हुए तो उसकी क्षमता 60 हजार की है। इन्दिरा गांधी कॉम्पलैक्स पर 669 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो केवल 14 हजार की क्षमता का स्टेडियम है। पांच हजार की क्षमता वाले डॉ. एस.बी. मुकर्जी स्वीमिंग पूल कॉम्पलैक्स पर 377 करोड़ रुपये खर्च हुए। डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर 149 करोड़ रुपये खर्च हुए, उसमें केवल 4,845 लोग बैठ सकते हैं। 7,862 की क्षमता वाले सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स पर 241 करोड़ रुपये खर्च हुए।...

देश की जनता को जानने दीजिए, कितने करोड़ रुपये खर्च हुए। यह टैक्स पेयर्स का पैसा है। हम भी सदन को उन्हीं के पैसे से चला रहे हैं। 210 करोड़ रुपये यमुना कॉम्पलैक्स पर खर्च हुए, जिसमें केवल 5,797 लोग बैठ सकते हैं। मैंने केवल कुछ की जानकारी आपको दी है। यह देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या स्टेडियम में बना है, जो 961 करोड़ रुपये वहां पर खर्च हुए और कुल मिलाकर 1899 करोड़ रुपये अगर इन खेलों का बजट था तो केवल एक स्टेडियम पर 961 करोड़ रुपये कैसे खर्च हुए, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं?

अगर क्रिकेट एसोसिएशन यह करके दिखा सकती हैं तो इतनी बड़ी सरकार क्यों नहीं करके दिखा सकती। अगर विजीलेंस कमीशन ने बात कही है और मेरे दोस्त मनीष जी ने अपनी बात में कहा कि यह तथ्यों से परे हैं, अगर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की बात कही गई और वैबसाइट पर यह लिखा है– Vigilance angle is suspected- मैं शायद इस सदन में नया हूं, मुझे लीगल जानकारी नहीं है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है? क्या अनियमितताएं बरती गई हैं, जो लगातार मीडिया में आया, वहां पर रिपोर्ट्स में आया, मैं लम्बी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप मुझे पढने़ का समय नहीं देंगी।...

मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मंत्री जी

को आप पूरा समय दीजिए, ताकि अपने जवाब में पूरे तथ्य वे सदन के सामने रख सकें। यहां पर सदन के लोगों ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि इससे देश के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में हजारों लोग झुग्गी–झोंपड़ियों से निकालकर बाहर भेजे जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये जा रहे हैं, ताकि वहां पर बम्बू की छोटी–छोटी पतरियों की जाफरी लगाई जाये, ताकि उस क्षेत्र को ढका जा सके और विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, वे झुग्गी–झोंपड़ियों को न देख सकें, मलबे के ढेर को न देख सकें। अगर वह 100 करोड़ रुपया झुग्गी–झोंपड़ियों की जगह नये घर बनाने पर खर्च किया जाता तो शायद उन लोगों को लाभ मिल सकता था। आज 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च केवल कनाट प्लेस पर किया गया। किस पर? प्राइवेट बिल्डिंग्स पर। 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च खान मार्केट पर किया गया। यह किसका पैसा है? टैक्स पेयर्स का पैसा है। यह प्राइवेट बिल्डिंग्स पर क्यों खर्च किया गया? उसका क्या लाभ मिलने वाला है? उसका क्या लाभ मिलने वाला है? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा।

मैडम, आज मैं सुबह साढ़े चार बजे ट्रेन से उतरकर वहां से आया हूं, आप पुरानी दिल्ली का हाल देखिए। वहां पर सिक्स लेन होते हुए भी सिंगल लेन पर चलने की जगह नहीं मिल पाती है। वहां ऐसे हालात हैं।

यह मांग की गयी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री प्रोब की जाए। भारतीय उच्चायोग ने अगर ई–मेल के साथ छेड़–छाड़ करने का आरोप ओ.सी. के अधिकारियों के ऊपर लगाया है, तो इसके तथ्यों की जानकारी इस सदन को मिलनी चाहिए। स्मैम जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी है, उसको लगभग 23 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही गयी। वह एक पैसे की स्पांसरशिप नहीं पा लाए। कुछ दिन पहले उसकी... स्पांसरशिप डील को कैंसिल कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि... मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर 23 प्रतिशत कमीशन उनको देने की बात कही गयी थी, तो क्या एक भी पैसा वह इकट्ठा करके ला सके? कांग्रेस पार्टी ने कई वर्षों तक एससी, एसटी के नाम पर कई चुनाव लड़े हैं। आज सात सौ करोड़ रूपए से ज्यादा के फंड डायवर्जन की बात कही जा रही है। उसकी जानकारी मैं मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहूंगा। स्टेडियम की कीमत वास्तविकता से कई गुना ज्यादा खर्च की गयी।

■■